— दैनिक समाचार पत्र —

सुमन पत्रिका

वर्ष: 03 अंक:231 | मूल्य: 2.00 रुपए | मंगलवार , 25 अगस्त 2026 | पृष्ठ: 4

आम चुनाव-2026 | नगरीय निकाय आम चुनाव-2026

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित

जयपुर(नि.सं.)। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से संबंधित अधिकारी जुड़े। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह ने सभी जिलों के अधिकारियों से सीधे संवाद कर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिलेवार चुनाव तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से चुनाव कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उनका समाधान किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने मतदाता सूचियों में संशोधन एवं अद्यतन की स्थिति, दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हों और दिव्यांग एवं अन्य जरूरतमंद मतदाताओं को मतदान के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

चुनाव कार्यो में लापरवाही पर जताई नाराजगी

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव तैयारियों में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरतने वाले जिलों एवं अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में चुनाव संबंधी कार्य पूरे करें और आयोग के निर्देशों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ पूरी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने चुनाव से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी समस्या का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा एवं अन्य अधिकारी का उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने कहा, विश्व में अक्षुण्ण रही है भारत की ज्ञान परम्परा

सम्पूर्ण जगत में प्राचीन भारतीय ज्ञान पर शोध व अध्ययन आवश्यक : राज्यपाल

जयपुर(नि.सं.)। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे उदयपुर में इतिहास विभाग, फैकल्टी ऑफ़ सोशल साइंस एन्ड हयूमेनिटीज़, पेसिफिक अकादमी ऑफ़ हायर एजुकेशन एन्ड रिसर्च विश्वविद्यालय, वेश्विक संस्कृत मंच एवं वैश्विक इतिहास मंच के तत्त्ववधान मे आयोजित प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा = ज्ञान एवं विज्ञानं के आधुनिक आयाम विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्टीय संगोष्ठी में सम्बोधित कर रहे थे। समापन समारोह में राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि विदेशी दार्शनिको भाषाविदो, लेखको ने भी भारतीय ज्ञान परम्परा भौतिक क्षमता, समृद्ध भाषा, वेश्विक दर्शन,परमाणुवाद के लोहे को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजो के आगमन से पहले भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन और विकास के लिए भारत में आठ लाख गुरुकुल, विद्यालय और आश्रम संचालित थे, जिनको पतन के कगार पर पंहुचाकर लार्ड मैकाले ने भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञानं पर आघात किया, जो भारत मेँ अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के रूप मेँ दृष्टाव्य है। इससे यहाँ के लघु कुटीर उद्योगो का पतन हुआ। उन्होंने अपने उदबोधन मेँ बप्पा रावल द्वारा विदेशी आक्रमणकरियो को भारत भूमि से बाहर निकालने से सम्बंधित विविध उद्धरण प्रस्तुत किए।

न्यूज इन बॉक्स

केरल की केजिया लिज मेजो बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया-2026

इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रजेंट करेंगी, बोलीं- यह मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी

जयपुर (नि.सं.)। केरल की केजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने अपनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस से हर किसी को इम्प्रेस किया। उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया-2025 मनिका विश्वकर्मा ने क्राउन पहनाया। केजिया अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस साल के अंत में प्यूर्टो रिको में होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दुनिया के विभिन्न देशों की ब्यूटी क्वीन हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश फर्स्ट रनर-अप और गुजरात की अनुश्री सातवलेकर सेकंड रनर-अप रहीं। जयपुर के जी-स्टूडियो में रविवार देर रात 'मिस यूनिवर्स इंडिया 2026' फिनाले आयोजित हुआ।

यूके की मॉली मैरी बक्ली बनीं मिस ओशियन वर्ल्ड

इंडोनेशिया की बेनिंग फज्रियानी फर्स्ट रनरअप रही, 20 देशों की मॉडल्स ने दिखाया टैलेंट

जयपुर। मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 के ग्रैंड फिनाले में यूनाइटेड किंगडम की मॉली मैरी बक्ली ने मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। जयपुर के मानसरोवर स्थित अनंत महल में अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट 'मिस ओशियन वर्ल्ड 2026' के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 20 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

भारत की हीना बनी सेकंड रनर-अप: इंडोनेशिया की बेनिंग फज्रियानी फर्स्ट रनरअप, भारत की हीना ठाकुर सेकंड रनर-अप, जापान की काना सागारा थर्ड रनरअप और जिम्बाब्वे की प्योरिटी तनात्स्वानाशे मकूबा फोर्थ रनर-अप रहीं। यह आयोजन टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज के तहत आयोजित किया गया।

जयपुर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल

राजस्थान में पहली बार विशेष पीडियाट्रिक एयरवे सीड वर्कशॉप, 70 से अधिक मेडिकल डेलीगेट्स ने लिया प्रशिक्षण

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में आज 6वीं विशेष पीडियाट्रिक एयरवे सीड वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और उन्नत पीडियाट्रिक एयरवे मैनेजमेंट पर केंद्रित गहन अकादमिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी एंड पेन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन एयरवे मैनेजमेंट फाउंडेशन (एएमएफ) के अकादमिक सहयोग तथा जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स (जेएसए) के सहयोग से किया गया।

कार्यशाला में 70 से अधिक मेडिकल डेलीगेट्स ने हैंड्स-ऑन सिमुलेशन ट्रेनिंग में भाग लिया। वर्कशॉप के मुख्य अतिथि पदमश्री डॉ माया टंडन एवं विशिष्ट अतिथि एस पी शर्मा रहें । एक दिवसीय कार्यक्रम में बाल चिकित्सा एयरवे आपात स्थितियों से जुड़ी व्यावहारिक एवं क्लिनिकल चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों के लिए पीडियाट्रिक एयरवे से संबंधित अकादमिक सत्र, नवीनतम एयरवे मैनेजमेंट उपकरणों के साथ मैनिकिन आधारित हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग तथा जटिल पीडियाट्रिक एयरवे परिस्थितियों पर इंटरैक्टिव केस डिस्कशन आयोजित किए गए।

वर्कशॉप में एयरवे मैनेजमेंट फाउंडेशन और जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स से जुड़े वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें डॉ. शक्ति दत्त शर्मा, (एएमएफ); डॉ. सुनील कुमार, सेक्रेटरी, (एएमएफ); डॉ. राजीव लोचन तिवारी, ऑर्गनाइजिंग प्रेसिडेंट; डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, प्रेसिडेंट, (जेएसए); डॉ. रितु शर्मा, ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी; डॉ. ज्योत्सना भार्गव, को-ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी; और डॉ. अखिल अग्रवाल, सेक्रेटरी, (जे एस ए) शामिल रहे।

अशोक नगर थाना पुलिस की कार्यवाही

पोकर गेम की आड़ में चल रहा था जुआघर:7 गिरफ्तार

माया गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जयपुर। डीएसटी जयपुर साउथ और अशोक नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कौशल पोकर गेम की आड़ में चल रहे जुआघर का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से मैनेजर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि रविवार को अशोक नगर थाना क्षेत्र स्थित माया गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर जी-22बी, कमला मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में कार्रवाई की गई। यहां ताश के पत्तों और टोकन के जरिए हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी भव्य (27) निवासी विद्युत नगर, चित्रकूट, दीपक सिंह (34) निवासी चकरोली, जगतपुरा, कौशल शाह (29) निवासी स्ट्रीटेंजर अपार्टमेंट, चेन्नई, अजय जोशी (21) निवासी भीमदत्त, नेपाल, आशीष दीवान (29) निवासी एसएमएस अस्पताल के सामने, जयपुर, ऋषभ बज (35) निवासी नालंदा विहार, दुर्गापुरा और प्रेम सिंह मोडई (30) निवासी शांति नगर, बागमती, काठमांडू है।

अमृता मेघवाल | बाबूलाल मेघवाल

भाजपा की पूर्व विधायक का तलाक रद्द:3 साल पहले दिए आदेश को कोर्ट ने एकतरफा माना

पति ने कहा- सोने की मणि नहीं चाहिए

जालोर(वि.सं.)। जालोर की फैमिली कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक अमृता मेघवाल और भाजपा एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बाबूलाल मेघवाल के तलाक को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने करीब 3 साल पहले पारित एकतरफा तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने माना कि अमृता मेघवाल को मामले में विधि अनुसार नोटिस की तामील नहीं हुई और उन्हें अपना पक्ष रखने का सही मौका नहीं मिला। आदेश के बाद बाबूलाल मेघवाल ने कहा- भले ही अमृता सोने की मणि हो, लेकिन अब मुझे यह मणि नहीं चाहिए। दरअसल, बाबूलाल मेघवाल ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद (तलाक) की याचिका 22 सितंबर 2022 को जालोर फैमिली कोर्ट में पेश की थी। अमृता को जयपुर के पुराने पते पर नोटिस भेजे गए।

बांसवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई

तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सहित 2 दलाल 4,000 रु. रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

आरोपी योगेंद्र सिंह वरिष्ठ सहायक | दलाल विठ्ठल | दलाल रतन सिंह

जयपुर / बांसवाड़ा(वि.सं.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बांसवाड़ा इकाई ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय बागीदौरा में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक योगेन्द्र सिंह भाटी और उसके लिए रिश्वत की रकम लेने वाले दो निजी व्यक्तियों (दलालों) रतनसिंह व विठ्ठल को 4,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गृह ऋण (होम लोन) से जुड़ी फाइलों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवाकर उपलब्ध कराने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। परिवादी ने एसीबी चौकी बांसवाड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को गृह ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण स्वीकृति से पहले आवेदकों की रजिस्ट्री को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवाना अनिवार्य होता है। तहसील कार्यालय बागीदौरा का वरिष्ठ सहायक योगेन्द्र सिंह भाटी दो फाइलों को रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवाकर पत्रावलियां सौंपने के बदले रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था। सत्यापन के दौरान 4,000 रुपये में तय हुआ सौदा शिकायत मिलने पर एसीबी द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया गया।

सत्यापन में पुष्टि: सत्यापन के दौरान आरोपी वरिष्ठ सहायक ने दोनों पत्रावलियों के एवज में 2,500 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से कुल 5,000 रुपये की मांग की। बाद में बातचीत के दौरान 500-500 रुपये कम करते हुए कुल 4,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमति बनी।

जाल बिछाकर दलालों सहित दबोचा, आवास की भी तलाशी

रिश्वत मांग की पुष्टि के बाद, एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और उप अधीक्षक पुलिस रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ट्रैप रचा गया।

ट्रैप के दौरान आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी ने परिवादी को 4,000 रुपये की रिश्वत राशि अपने परिचित रतनसिंह (दलाल) को देकर विठ्ठल (दलाल) तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

पानी पीने गया भाई डूबा,बचाने गई 2-बहनों की भी मौत

खेत से घर नहीं लौटे तो पहुंचे परिजन; 3 दिन पहले मां का हुआ था निधन

जोधपुर(वि.सं.)। जोधपुर जिले में चौकड़ी गांव के एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से भाई और 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। तीनों घर से खेत पहुंचे थे। यहां भाई को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए डिग्गी के पास गया। पैर फिसलने से वह डिग्गी में गिर गया। छोटे भाई को डूबता देख चचेरी बहनें उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में कूद गईं। डिग्गी में गहराई के कारण तीनों ही डूब गए। हादसा बोरुंदा थाना इलाके में रविवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच हुआ। परिजनों के अनुसार- सुमन (12) पुत्री भिया, रेखा (16) पुत्री नाथूराम और प्रवीण (8) पुत्र महेंद्र चचेरे भाई-बहन थे।

नगर निगम जयपुर के आम चुनाव-2026

नगर निगम जयपुर के आम चुनाव-2026 के लिए नामांकन पत्र हेतु 15 प्राप्ति स्थलों का निर्धारण

जयपुर(नि.सं.)। नगर निगम जयपुर के आम चुनाव-2026 के लिए नगर निगम जयपुर के समस्त वार्डो में आम चुनाव के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित वार्डो के नामांकन पत्र प्राप्त करने एवं नामांकन प्राप्ति के पश्चात निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाही संपादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्ड संख्या 1 से 10 के लिए कार्यालय रीको रोड नंबर 05, वी.के.आई., सीकर रोड, 11 से 20 के लिए कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लॉट नंबर 370, वी.के.आई. एरिया, मुरलीपुरा, 21 से 30 के लिए कार्यालय उपायुक्त नगर निगम झोटवाड़ा जोन, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, 31 से 40 के लिए शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय (अंग्रेजी माध्यम), खातीपुरा, 41 से 50 के लिए उपखण्ड कार्यालय, सांगानेर तथा 51 से 60 के लिए पंचायत समिति कार्यालय, सांगानेर प्राप्ति स्थल निर्धारित किए गए हैं।

मतदाताओं, प्रत्याशियों को किया अलर्ट | राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नगर निकाय चुनाव में साइबर ठगों से सावधान रहें

फर्जी वोटर लिंक, OTP और क्यूआरकोड से हो सकती है ठगी

जयपुर(नि.सं.)। नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के दौरान साइबर ठग मतदाताओं, चुनाव प्रत्याशियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को निशाना बनाकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाएं फैला सकते हैं। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को सतर्क रहने की अपील की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं, श्री वी.के. सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा द्वारा जारी साइबर एडवायजरी अनुसार चुनाव के दौरान विशेष रूप से फर्जी लिंक, क्यूआर कोड, फिशिंग ई-मेल और डीपफेक/फेक न्यूज के प्रति सावधानी बरतने की अपील की गई है।

वोटर लिस्ट में नाम देखें-ऐसे फर्जी लिंक से रहें सावधान

साइबर ठग WhatsApp या SMS के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में देखें, आपका पोलिंग बूथ बदल गया है जैसे संदेश

भेजकर फर्जी लिंक पर क्लिक करा सकते हैं। ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें। मतदाता सूची अथवा मतदान संबंधी जानकारी के लिए केवल State Election Commission, Rajasthan और CEO Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

OTP मांगने वाला कोई भी अधिकारी हो सकता है साइबर ठग

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर वोटर कार्ड अपडेट, सत्यापन अथवा अन्य चुनावी प्रक्रिया के नाम पर फोन करने वाले व्यक्ति को OTP, बैंक विवरण, PI PIN या अन्य निजी जानकारी साझा नहीं करें। याद रखें–OTP किसी के साथ साझा करना साइबर ठगी का कारण बन सकता है।

वायरल वीडियो और ऑडियो पर तुरंत विश्वास न करें

चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नेताओं के नाम से फर्जी वीडियो, ऑडियो, भाषण एवं डीपफेक सामग्री वायरल की जा

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

चीनी उत्पादन में आगे तो मिठास पर पहरा क्यों?

भारत दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है, फिर भी चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर अतिरिक्त नियंत्रण की जरूरत क्यों पड़ी, यह गंभीर सवाल है। एथेनॉल उत्पादन को लेकर सरकार की नीति पर विपक्ष के आरोपों के बीच अब भंडारण सीमा का फैसला किया गया है। जरूरत केवल नियम बनाने की नहीं, बल्कि उपभोक्ता को वास्तविक राहत देने और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक दबाव से बचाने की है।

> **कीमतों पर नियंत्रण के लिए पंद्रह दिन की भंडारण सीमा का फैसला, लेकिन एथेनॉल नीति से लेकर बाजार में वास्तविक उपलब्धता तक कई सवालों के जवाब जरूरी है।**

कारोबारियों के लिए चीनी का पंद्रह दिन का भंडारण तय करने का सरकारी फैसला पहली नजर में बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण रखने की कोशिश दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस कदम से वास्तव में चीनी सस्ती होगी और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी? केवल भंडारण सीमा तय कर देने से बाजार की सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। चीनी का बाजार केवल चीनी मिलों और बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं है। इसके साथ किसान, परिवहन व्यवस्था, थोक विक्रेता, किराना कारोबारी और अंतत: वह आम परिवार जुड़ा है, जिसकी रसोई में हर महीने चीनी की जरूरत होती है। चीनी महंगी होने का असर केवल चाय की मिठास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिठाई, बिस्कुट, पेय पदार्थ और कई अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। यदि पंद्रह दिन की भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना और बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस व्यवस्था का सबसे अधिक बोझ छोटे कारोबारियों पर न पड़े। बड़े कारोबारी नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से निपटने के रास्ते निकाल लेते हैं, जबकि छोटे व्यापारी निरीक्षण, कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक दबाव का आसानी से निशाना बन सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो बाजार को संतुलित करने के बजाय यह व्यवस्था छोटे कारोबारियों के लिए नई परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए भंडारण सीमा लागू करते समय निगरानी व्यवस्था स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। नियम सभी पर समान रूप से लागू हों और कार्रवाई का आधार वास्तविक जमाखोरी हो, न कि केवल भंडारण की मात्रा। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ऐसे में उत्पादन और खपत के बीच संतुलन को लेकर सामान्य परिस्थितियों में बहुत अधिक चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर सरकार को अतिरिक्त कदम उठाने पड़े, यह सवाल स्वाभाविक है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ समय में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतों में बढ़ोतरी हुई। उनका तर्क है कि चीनी उत्पादन का एक हिस्सा एथेनॉल की ओर जाने से बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा पर असर पड़ा और अब उसकी भरपाई के लिए आयात तथा भंडारण सीमा जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन आरोपों की वास्तविकता आंकड़ों और स्वतंत्र समीक्षा के आधार पर स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि एथेनॉल नीति का चीनी के उत्पादन, उपलब्धता और कीमतों पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ा है। इससे जनता के बीच पैदा हो रहे भ्रम को भी दूर किया जा सकेगा। नीतियों की सफलता का वास्तविक पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि कितने नियम बनाए गए या कितने आंकड़े प्रस्तुत किए गए। महत्वपूर्ण यह है कि बाजार में चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और आम उपभोक्ता को उचित कीमत पर मिले। सरकार को बाजार की नियमित निगरानी के साथ आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ छोटे कारोबारियों को अनावश्यक प्रशासनिक दबाव से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत जैसा प्रमुख चीनी उत्पादक देश यदि अपनी घरेलू जरूरतों के लिए उपलब्धता और कीमतों को लेकर बार-बार अतिरिक्त नियंत्रण का सहारा लेता है, तो उसकी नीतियों की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। एथेनॉल उत्पादन, चीनी का भंडारण और आयात—इन सभी के बीच संतुलन बनाना होगा। अंतत: जनता को आभासी आंकड़े नहीं, बल्कि बाजार में पर्याप्त चीनी और उसकी उचित कीमत के रूप में वास्तविक राहत चाहिए।

सड़कों पर उतरा युवा तो क्यों झुकने लगती हैं सरकारें?

याशराज यादव

दिल्ली के जंतर-मंतर आंदोलन के पीछे कौन था, राजनीतिक संगठन किसके इशारे पर काम कर रहे थे और इन आंदोलनों के राजनीतिक लक्ष्य क्या थे, इन सवालों से अलग एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि युवाओं ने इन आंदोलनों से एक संदेश ग्रहण किया है—यदि अपनी मांग मनवानी है तो सड़कों पर उतरना होगा और वह भी बिना भय अथवा किसी सौदेबाजी की मंशा के। यही कारण है कि खुद को सख्त दिखाने वाली सरकारें भी ऐसे आंदोलनों के सामने असहज नजर आ रही हैं। जेन जी और जेन अल्फा के आंदोलनों का यह तरीका भले ही कुछ लोगों को अराजकता, दबाव की राजनीति या प्रायोजित आंदोलन जैसा दिखाई दे, लेकिन कई मामलों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इन आंदोलनों की एक खास बात यह है कि युवा सामान्यत: राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों को अपने आंदोलनों से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि कुछ मामलों में विपक्षी दल खुलकर उनके समर्थन में भी आए हैं। इससे युवाओं और पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच बदलते संबंधों की तस्वीर सामने आती है। दिल्ली में पैलेट गन से घायल युवक के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीब पांच घंटे तक चला धरना भी इसी सिलसिले की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग स्वीकार की। जंतर-मंतर पर जेन जी आंदोलन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल और उससे एक युवक के घायल होने का मामला पहले से विवादों में था। सरकार और पुलिस की ओर से कहा जाता रहा कि आंदोलन के दौरान पैलेट गन नहीं चलाई गई। दिल्ली पुलिस ने भी इससे इनकार किया। इसके बावजूद राहुल गांधी घायल युवक को सामने लेकर आए, जिसके शरीर में पैलेट गन के कई छर्रे लगे होने की बात सामने आई। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में भी इस संबंध में तथ्य सामने आने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि यदि पैलेट गन नहीं चलाई गई तो युवक के शरीर में उसके छर्रे कैसे पहुंचे? दूसरी ओर, आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर उसके हलफनामे से असंतुष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने अलग जांच समिति बनाने की बात कही है। शुरुआत में पुलिस इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से बचती रही। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर राजनीतिक आरोप लगाए, लेकिन जब वह अपनी मांग पर अड़े रहे तो बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। सवाल यह है कि प्राथमिकी पहले ही दर्ज कर ली जाती तो क्या इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा होता? अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी का अर्थ ही यही है कि जांच के दौरान आरोपित की पहचान की जा सकती है। यदि 14 अगस्त को ही घायल युवक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाती तो पुलिस यह कह सकती थी कि पैलेट गन किसने और किन परिस्थितियों में चलाई, इसकी जांच जारी है। इसके बजाय मामले ने राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का रूप ले लिया। जंतर-मंतर के आंदोलन का असर मध्यप्रदेश में भी जेन जी और जेन अल्फा के तेवरों में दिखाई दे रहा है। बीते दस दिनों में राज्य में ऐसे छह बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें बच्चे और युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और प्रशासन को फैसले बदलने या तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंदौर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की दिव्यांग छात्रा से मेस शुल्क की कथित अधिक वसूली, छिंदवाड़ा के दूरस्थ गांव बीच बहरी में शिक्षकों के निर्धारित समय तक अध्यापन नहीं करने, विदिशा के सिरोंज में बस किराया घटाने, भोपाल के डीएमएस विद्यालय के केंद्रीय विद्यालय में विलय पर रोक तथा धार के निसरपुर में माता शबरी छात्रावास की छात्राओं द्वारा खराब भोजन के विरोध में आधी रात थाने का घेराव जैसे मामले इसके उदाहरण हैं। छात्राओं के विरोध के बाद छात्रावास अधीक्षिका को निलंबित करना पड़ा। उज्जैन में लड़कियों के विद्यालय को सांदीपनि विद्यालय के नाम पर करीब 12 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने का फैसला भी विरोध के बाद वापस लिया गया। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह प्रवृत्ति आगे और तेज हो सकती है।

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों और अभ्यर्थियों का 25 दिनों तक चला आंदोलन भी आंशिक रूप से सफल रहा। राज्य सरकार ने 2014 से 2025 के बीच हुई सरकारी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग स्वीकार की, लेकिन बाद में चयनित और नियुक्त हो चुके दो हजार से अधिक कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगाते हुए सवाल उठाया कि पिछली तारीख से परीक्षाओं को कैसे रद्द किया जा सकता है। मामला आगे सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है। इसके बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि दो महीने में मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। हालांकि आंदोलनकारियों की सभी मांगें स्वीकार नहीं की गईं। पूर्व की 22 परीक्षाओं को रद्द करने और छह नई परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पर सरकार ने सहमति जताई, लेकिन सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग स्वीकार नहीं की गई। जांच राज्य की अपराध जांच शाखा से कराने का फैसला हुआ। झारखंड के आंदोलन को भाजपा का समर्थन मिला। लेकिन यहां एक राजनीतिक सवाल भी महत्वपूर्ण है। जिनमें 2014 से 2019 के बीच हुई भर्तियां भी शामिल हैं, वह अवधि राज्य में भाजपा शासन की थी। उस दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 33,184 सरकारी पदों पर भर्तियां हुई थीं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या आंदोलनकारी उस दौर में हुई नियुक्तियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं? सरकारों के सामने चुनौती केवल यह नहीं है कि वे युवाओं के आंदोलनों को कैसे रोकें। उससे बड़ा सवाल यह है कि वैध शिकायतों और ऐसी मांगों के बीच अंतर कैसे किया जाए, जिनका असर पूरी व्यवस्था पर पड़ सकता है।यदि बिना गहन जांच के अतीत की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग स्वीकार की जाने लगे तो मेहनत से परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले हजारों लोगों के साथ अन्याय हो सकता है।

मंदिर प्रबंधन पर उठे सवालों का जवाबदेह समाधान जरूरी

> **अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का विवाद अब मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णयों तक पहुंच गया है। जांच की निष्पक्षता, न्यास की जिम्मेदारी और निर्माण समिति के कामकाज को लेकर उठ रहे सवाल आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान की व्यवस्था पर गंभीर विमर्श की मांग करते हैं। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें हर निर्णय पारदर्शी हो और किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय की जा सके।**

पवन दाधीच

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ उनके भरोसे को भी प्रभावित किया है। चिंता की बात यह है कि जिन लोगों पर चढ़ावे का हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं से जुड़े लोगों पर कथित गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। माना जा रहा था कि विशेष जांच दल की जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अब जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खबरों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के तत्कालीन प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अब विवाद का दायरा चढ़ावे की कथित चोरी से आगे बढ़कर राम मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णयों तक पहुंच गया है। दान राशि में गड़बड़ियों को लेकर स्वयं सवालों के घेरे में रहे न्यास के पूर्व महासचिव चंपत राय ने निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर मनमाने तरीके से निर्णय लेने के आरोप लगाए हैं। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि मंदिर के कार्य और प्रबंधन से जुड़ी ऐसी कितनी परतें हैं, जिनकी पड़ताल अभी बाकी है। मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाला प्रत्येक रुपया श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए उसके प्रबंधन में किसी भी तरह की अनियमितता को सामान्य वित्तीय गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि न्यास के पदाधिकारी शुरुआत में चढ़ावा चोरी के आरोपों को नकारते रहे, लेकिन आंतरिक जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने के बाद जिम्मेदारी लेने के बजाय सरकार से जांच कराने की मांग की गई। इसके बाद विशेष जांच दल का गठन हुआ। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि चढ़ावे में कथित चोरी लंबे समय तक होती रही तो न्यास के पदाधिकारियों और निगरानी व्यवस्था को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या निगरानी के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही थी? करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। केवल पद से हट जाना या इस्तीफा देना नैतिक जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना था कि उनकी जिम्मेदारी निर्माण कार्यों की निगरानी तक सीमित है। उन्होंने यह भी माना था कि दान पात्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में कमी रही, जिसके कारण कुछ लोगों को वित्तीय हेराफेरी का अवसर मिला। अब पूर्व महासचिव चंपत राय द्वारा उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने से विवाद का एक नया पक्ष सामने आया है। चंपत राय का दावा है कि निर्माण कार्यों से जुड़े कई फैसले समिति में सर्वसम्मति से किए गए थे, लेकिन बाद में नृपेंद्र मिश्रा के कहने पर उनमें बदलाव किए गए। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल व्यक्तियों के बीच मतभेद का मामला नहीं रह जाता, बल्कि मंदिर निर्माण की निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और संस्थागत व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े करता है। हालांकि आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय में आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए उसके निर्माण और प्रबंधन से जुड़ा प्रत्येक निर्णय निर्धारित प्रक्रिया, स्पष्ट नियमों और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में होना चाहिए। आस्था से जुड़े संस्थान में पारदर्शिता का महत्व और बढ़ जाता है। यहां वित्तीय लेन-देन से लेकर निर्माण संबंधी निर्णयों तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बजाय संस्थागत प्रक्रिया सर्वोच्च हो। राम मंदिर के प्रबंधन को लेकर उठे सवालों का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और स्पष्ट जवाबदेही से ही संभव है। चढ़ावे की सुरक्षा, वित्तीय लेखा-जोखा, निर्माण कार्यों की निगरानी और निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। मंदिर से जुड़ी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां श्रद्धालुओं को यह भरोसा रहे कि उनकी आस्था से प्राप्त धन और उससे जुड़े प्रत्येक संसाधन का उपयोग पूरी ईमानदारी से हो रहा है। यही नहीं, यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी भी स्पष्ट रूप से तय हो। राम मंदिर केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसलिए इसके प्रबंधन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। अब जरूरत ऐसी व्यवस्था कायम करने की है, जो भविष्य में किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न छोड़े और लोगों के विश्वास को और मजबूत करे।

चंदे की अर्थव्यवस्था

जेब आपकी, पुण्य हमारा

पूनम

चंदा अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द है। एक चंदा आसमान में है, जिसकी चांदनी में ठंडक है और दूसरा जमीन पर, जिसमें पैसे की गर्मी है। आसमान वाला चंदा बिना कुछ मांगे आता-जाता है, जबकि जमीन वाला चंदा मौसम-बेमौसम पर्ची, रसीद, मुस्कान या आत्मीयता लेकर सामने आ खड़ा होता है। चंदा मांगने वाला अक्सर इस तरह पेश आता है, जैसे सामने वाले के पास पैसा नहीं बल्कि समाज का कोई अधूरा कर्तव्य रखा हो। बात केवल रकम देने की नहीं रहती, बल्कि उसे पुण्य, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया जाता है।हर शहर, कस्बे और गांव में ऐसे चंदा वीर मिल जाते हैं, जिनके लिए चंदा मांगना महज जरूरत नहीं बल्कि एक कला है। गांव के चंदा वीर गुजरी गुरु इस कला के पुराने जानकार हैं। उनके अनुसार चंदा मांगने वाले को सामने वाले के पास पहुंचते ही ऐसी विनम्रता दिखानी चाहिए कि उसकी सारी इंद्रियां पहचानने में व्यस्त हो जाएं। साथ आए लोगों को भी ऐसा भाव रखना चाहिए, जैसे वे किसी गंभीर सामाजिक दायित्व के निर्वहन में शामिल हों। उनका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र रकम बताने से जुड़ा है। उनका मानना है कि बहुत कम रकम बताइए, ताकि सामने वाला स्वयं अधिक देने की पेशकश कर दे। सामाजिक प्रतिष्ठा का हल्का-सा स्मरण भी काम कर जाता है। सामने वाला जेब से पहले अपना कद देखने लगता है और फिर उसी के अनुरूप चंदा निकालता है। यही कारण है कि दो हजार रुपये मांगकर पांच हजार की रसीद कटवा लेना चंदा मांगने वाले की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। चंदा खुद को शायद ही कभी चंदा कहता है। वह सहयोग, योगदान, समर्पण और जनभागीदारी बन जाता है। पैसा वही रहता है, केवल नाम बदल जाता है। इस व्यवस्था का सबसे सुविधाजनक वाक्य है—'जितना बन पड़े।' इसमें पांच रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की गुंजाइश रहती है। पहले रसीद बुक आती थी, अब मोबाइल में क्यूआर कोड आ जाता है। श्रद्धा भी डिजिटल हो गई है। पैसा भेजते ही संदेश आता है कि लेन-देन सफल रहा। यानी चंदा देने वाला भी सफल घोषित हो जाता है। चंदा केवल आयोजन का खर्च नहीं जुटाता, वह सामाजिक संबंधों का भी हिसाब तय करता है। जिसने अधिक दिया, उसे मंच पर आगे की कुर्सी मिलती है। जिसने कम दिया, उसे पीछे जगह मिलती है और जिसने कुछ नहीं दिया, वह भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। चंदे की अपनी राजनीति भी होती है—किसके घर पहले जाना है, किससे कितनी रकम मांगी जा सकती है, किससे पुराना संबंध है और भविष्य में किससे काम पड़ सकता है। इन सबका हिसाब चंदे की सफलता में रकम के हिसाब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंदा विश्वास पर चलता है और जहां विश्वास होता है, वहां हिसाब अक्सर छोटा हो जाता है। बड़े आयोजन के लिए बड़ा खर्च बताया जाता है और खर्च जितना बड़ा होता जाता है, हिसाब पूछना उतना ही असहज माना जाने लगता है। चंदा देने वाला भी बहुत कुछ समझता है और लेने वाला भी। दोनों के बीच एक मौन समझौता रहता है। देने वाला जानता है कि पूरी रकम शायद उसी काम में न लगे, जिसके नाम पर ली गई है, और लेने वाला जानता है कि देने वाला यह बात समझता है। फिर भी दोनों इसे सार्वजनिक नहीं करते। व्यंग्य की धार यहीं सबसे तेज हो जाती है—चंदा केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, अपराधबोध, दिखावे और संबंधों को साधने का माध्यम भी बन गया है।

सरकारी विद्यालयों की बदहाली दूर करना समय की मांग

पवन गुर्जर

सरकारी विद्यालयों की दशा की ओर विभिन्न माध्यमों से ध्यान आकर्षित होना अच्छी बात है। कहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र स्वयं उनकी समस्याएं सामने ला रहे हैं तो कहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उनकी स्थिति को उजागर कर रहे हैं। भले ही इनके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हों, लेकिन सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर चर्चा इसलिए जरूरी है, क्योंकि वहां पठन-पाठन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता लंबे समय से बनी हुई है। एक समय देश में अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालयों पर ही निर्भर थे। उस समय उनकी स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक थी। जैसे-जैसे निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ती गई, सरकारी विद्यालय उपेक्षित होते चले गए। सरकारें इन विद्यालयों पर धन खर्च कर रही हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उस धन का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं।विडंबना यह है कि समय के साथ सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में विद्यालयों, विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों के पास उचित भवन तक नहीं हैं। अनेक विद्यालय जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे हैं, जबकि कुछ के पास विद्यालय भवन के नाम पर पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। कई विद्यालय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव से भी जूझ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की समस्या केवल भवन, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं तक सीमित नहीं है। शिक्षकों की कमी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी शैक्षणिक

व्यवस्था चल रही है। ऐसे संसाधनविहीन विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल है। सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा दूर नहीं होने का असर अभिभावकों की पसंद पर भी पड़ रहा है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अनेक परिवार अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने के लिए विवश हैं। सामान्यत: वही अभिभावक सरकारी विद्यालयों का रुख करते हैं, जिनके पास निजी विद्यालयों का विकल्प नहीं होता। यह स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों के घटते भरोसे को दर्शाती है। सरकारी विद्यालयों की खराब स्थिति कोई नई समस्या नहीं है। समय-समय पर उनकी बदहाली सामने आती रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना भी जरूरी है कि योजनाओं और उनके लिए आवंटित संसाधनों का वास्तविक लाभ विद्यालयों तक पहुंच रहा है या नहीं। राज्य सरकारों को सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने होंगे। विद्यालयों को पर्याप्त भवन, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों की कमी भी दूर करनी होगी। पठन-पाठन का स्तर ऐसा बनाना होगा कि अभिभावक केवल मजबूरी में नहीं, बल्कि भरोसे के साथ अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें। केंद्र सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी व्यवस्था बने और बेहतर उदाहरण सामने आएं। यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनाना है तो शिक्षा की बुनियाद मजबूत करनी होगी। गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था इस लक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिलाओं में से एक है।

साधारण मोमबत्ती में छिपा विज्ञान का संसार, जिज्ञासा से खुलते हैं प्रकृति के रहस्य

वेद व्यास

कल्पना कीजिए कि हमारे सामने एक मोमबत्ती जल रही है। देखने में यह कितनी साधारण वस्तु है, लेकिन यदि हम इसके भौतिक घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो इसके भीतर प्रकृति के कितने ही रहस्य छिपे दिखाई देते हैं। मेरे विचार में विज्ञान के अध्ययन में प्रवेश करने के लिए इससे अधिक सरल और खुला मार्ग मिलना कठिन है।

मोमबत्ती को जलते हुए देखना केवल प्रकाश को देखना नहीं है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि प्रकाश कहां से आता है, लौ का आकार ऐसा क्यों है, मोम किस प्रकार पिघलता है और जलने के बाद उसका क्या रूपांतरण होता है। जब हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, तो पाते हैं कि इस छोटी-सी लौ में प्रकृति के अनेक नियम एक साथ काम कर रहे होते हैं। दरअसल, मोम स्वयं सीधे उस रूप में नहीं जलता, जिस रूप में हम उसे देखते हैं। गर्मी उसे पिघलाती है। पिघला हुआ पदार्थ बत्ती के सहारे ऊपर उठता है और फिर वाष्प में बदल जाता है। वास्तव में वही वाष्प जलती है। इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा, पदार्थ और वायु का अद्भुत संबंध दिखाई देता है। लौ को और ध्यान से देखिए। उसका सबसे चमकीला भाग भी हमें एक कहानी सुनाता है। उसमें उपस्थित सूक्ष्म कार्बन कण गर्म होकर प्रकाश देते हैं। मोमबत्ती हमें सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि उसके जलने के दौरान कई तरह के रासायनिक और भौतिक बदलाव होते हैं। इसकी लौ को समझते-समझते हम पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जान सकते हैं। ऑक्सीजन हमें हवा की प्रकृति समझाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध पौधों और इंसानों से है। मेरा मानना है कि साधारण वस्तुओं को असाधारण तरीके से देखना ही विज्ञान की शुरुआत है। एक मोमबत्ती भी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास की दुनिया रहस्यों से भरी है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उसे ध्यान से देखें, प्रश्न पूछें और उत्तर खोजने का साहस रखें। यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का असली सौंदर्य है।

विधिक जागरूकता के साथ जनकल्याणकारी शिविर, 45 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

मुमन पत्रिका

चौथ का बरवाड़ा। पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा के सभागार एवं परिसर में सोमवार को तालुका विधिक सेवा समिति, चौथ का बरवाड़ा के तत्वावधान में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम तथा जन कल्याणकारी शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती नेहा मौर्य ने की। सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में श्रीमती नेहा मौर्य ने नालसा की 'मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2024' के बारे में

जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना तथा आवश्यक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराकर न्याय तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि अपराध से प्रभावित पात्र पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को नियमानुसार प्रतिकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के माध्यम से पीड़ितों एवं उनके परिवारों को आर्थिक राहत तथा पुनर्वास में सहायता प्रदान की जाती है। इस दौरान पात्रता, प्रतिकर प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार शर्मा ने भी उपस्थित लोगों को संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए जरूरतमंद लोगों को विधिक सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।

विभिन्न विभागों ने दी योजनाओं की जानकारी

पंचायत समिति परिसर में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना अधिकारी गौतम ऋषि मीणा, शिक्षा विभाग से चंद्र मोनिका स्वामी, चिकित्सा विभाग से अशफाक अहमद, कृषि विभाग से लोकेश कुमार मीणा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से फूल सिंह मीणा, पंचायत समिति से कन्हैया लाल मीणा, विद्युत विभाग से दिलराज तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से लेखराज मीना सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने आमजन को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी। शिविर में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से पीएलवी मोर सिंह गुर्जर, आशाराम नागर एवं चंदन मीना ने स्टॉल के माध्यम से नालसा एवं लालसा की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान करीब 45 लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ या सहायता उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में लगभग 100 से 110 लोगों की उपस्थिति रही। शिविर का उद्देश्य आमजन, विशेषकर कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर तथा सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं एवं न्यायिक सेवाओं से जोड़ना रहा।

उड़द की फसल को कीटों-रोगों से बचाएं - डॉ. जितेन्द्र शर्मा

मुमन पत्रिका

टोंक । वर्तमान में उड़द की फसल पर झुलसा रोग, पीला मोजेक रोग एवं फली व पत्ती छेदक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा हैं। एग्री क्लिनिक एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला टोंक के इंचार्ज डॉ. जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि कीटों व रोगों से बचाव के लिए छिड़काव/भुरकाव करें एवं कृषि रसायनों को उपयोग करते समय सदैव हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क तथा पूरे वस्त्र पहने । पीला मोजेक रोग के प्रसार को रोकने के लिए रोगी पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर देवें एवं रोग वाहक रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए 150 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. अथवा 200 ग्राम फ्लोनीकामिड 50 प्रतिशत डब्ल्यू.जी. अथवा 1 लीटर डायमिथोएट 30 ई.सी. का घोल बनाकर प्रति

हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें एवं दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। फली व पत्ती छेदक कीटों से बचाव के लिए क्यूनालफॉस 25 ई. सी. एक लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से फूल व फली आते ही छिड़किए अथवा क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर अथवा फेनवेलेरेट 0.4 प्रतिशत चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से का भुरकाव करें। आवश्यकता हो तो हर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव/भुरकाव दोहरावें। जीवाणुज पत्ती धब्बा रोग में छोटे गहरी भूरे रंग के धब्बे पत्तों पर तथा प्रकोप बढ़ने पर फलियों और तने पर भी दिखाई देते हैं इससे पौधे मुरझा जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लिन एवं 20 ग्राम ताम्रयुक्त कवकनाशी (कॉपर ऑक्सीक्लोराइड) का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता हो तो छिड़काव दोहरायें। झुलसा रोग से बचाव के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही इसके नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम एक ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर पुनः करें।

नगर निकाय आम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं, मतदान कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन सम्पन्न

मुमन पत्रिका

टोंक । नगर निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) टीना डाबी कि उपस्थिति में 24 अगस्त सोमवार को एनआईसी कक्ष में मतदान कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। प्रथम रेंडमाइजेशन के दौरान नगर निकाय आम चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी का रेंडमाइजेशन किया गया। रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी एवं निष्पक्ष

तरीके से सम्पन्न कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आगामी चरणों में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों के गठन एवं अन्य आवश्यक निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। प्रथम रेंडमाइजेशन के माध्यम से मतदान कार्मिकों की निर्वाचन प्रक्रिया में ड्यूटी निर्धारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम पूरा हुआ। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार मीणा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुशील कुमार अग्रवाल एवं डीएमओ नितेश कुमार जैन सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मृतक के आश्रित को सहायता राशि स्वीकृत की

जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई स्थगित

मुमन पत्रिका

टोंक । टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी ने दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जिला कलेक्टर डाबी ने बताया कि दुर्घटना में मृतक कुलदीप पुत्र रामकिशोर मेहरा, निवासी

गोल डूंगरी, तहसील व जिला टोंक के आश्रित को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की हैं।

जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई स्थगित :-

राज्य सरकार के जन अभियोग निराकरण विभाग के निर्देशों के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता के मध्यनजर सितम्बर माह में आयोजित होने वाली जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई स्थगित की गई है।

24 घंटे में 300 किमी पीछा कर चोरी हुआ ट्रक बरामद, 30 लाख का जिम सामान सुरक्षित

मुमन पत्रिका

टोंक। दत्तवास थाना पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और टोल टैक्स फुटेज की मदद से चोरी हुए ट्रक का करीब 300 किलोमीटर तक पीछा कर महज 24 घंटे में ट्रक सहित करीब 30 लाख रुपए कीमत का जिम सामान बरामद किया है। पुलिस को भनक लगने पर अज्ञात चोर ट्रक को कोटा जिले के मंडाना थाना क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशानुसार एएसपी टोंक मुख्यालय

रतनलाल भार्गव एवं सीओ निवाई रविप्रकाश शर्मा के सुपरविजन में एसएचओ दत्तवास निरमा मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम में हेड कांस्टेबल नहार सिंह, हेड कांस्टेबल रामबिलास, कांस्टेबल बलवंत एवं कांस्टेबल नरेंद्र शामिल रहे। पुलिस के अनुसार 20 अगस्त की रात होटल रावत पैलेस, एनएच-11ए से आईसर ट्रक नंबर RJ-14-GK-3907 चोरी हो गया था। ट्रक में करीब 30 लाख रुपए कीमत का जिम का सामान भरा हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी संसाधनों एवं विभिन्न टोल नाकों के फुटेज खंगालते हुए ट्रक की लोकेशन का पता लगाया और करीब 300 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। पुलिस टीम ने ट्रक को मंडाना थाना क्षेत्र, जिला कोटा ग्रामीण में लावारिस हालत में बरामद किया। बताया गया कि पुलिस की भनक लगने पर अज्ञात चोर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक एवं उसमें भरे जिम सामान को फर्द बरामदगी के जरिए कब्जे में लेकर सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर में खड़ा करवाया है। दत्तवास एसएचओ निरमा मीना ने बताया कि मामले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान एवं तलाश जारी है। कार्रवाई में मंडाना थाना, जिला कोटा ग्रामीण के एसएचओ सुमेर सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश एवं कांस्टेबल श्रवण जाट का भी विशेष सहयोग रहा।

पुलिस थाना निवाई ने लोहे का गण्डासानुमा अवैध धारदार हथियार जब्त सहित आरोपी राजाराम उर्फ राजू प्रजापत झिलाय को किया गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज

मुमन पत्रिका

टोंक । पुलिस अधीक्षक टोंक रोशन मीना के निर्देशानुसार व एएसपी टोंक मुख्यालय रतन लाल भार्गव एवं सीओ निवाई रविप्रकाश शर्मा के निकट सुपर विजन में एसएचओ घासीराम मीना सीआई के नेतृत्व मे गठित विशेष टीम में सउनि जीतपाल , हैड कांस्टेबल शंकरलाल , कॉस्टेबल मनोज, कॉस्टेबल मनप्रीत सिंह को दिनांक 23 अगस्त को लॉकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु ईलाका थाना में रवाना किया गया। गश्त के दौरान गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये ग्राम झिलाई मे सिरोही रोड पर नरसी सागर तालाब की पाल के पास से आरोपी राजाराम उर्फ राजू प्रजापत पुत्र जगदीश प्रजापत जाति कुम्हार (33) निवासी कुम्हारों का मोहल्ला झिलाय पुलिस थाना निवाई जिला टोंक

द्वारा बिना लाईसेन्स के लोहे का गण्डासानुमा धारदार हथियार लेकर घुमता पाया जाने पर आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से लोहे का गण्डासानुमा धारदार हथियार को जब्त किया गया। आरोपी के विरूध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया।

1989 के कोर्ट आदेश के बाद भी सरकारी गोदामों पर कब्जे का आरोप

जौहरी बाजार मंडी में मचा हड़कंप, वैध वेंडर्स बोले कब्जा नहीं हटा तो आंदोलन

मुमन पत्रिका

जयपुर। जौहरी बाजार फल-सब्जी माशाखोर एसोसिएशन ने जौहरी बाजार मंडी में नगर निगम के स्वामित्व वाले सहकारिता बीज गोदाम संख्या 40 सहित अन्य सरकारी गोदामों पर कथित अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि लंबे समय से बंद पड़े सरकारी गोदामों पर कुछ लोगों ने कथित रूप से कब्जा कर लिया है, जिससे वैध वेंडर्स में रोष है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी ने बताया कि 12 जुलाई 1989 को माननीय न्यायालय ने मंडी के 101 वैध व्यापारियों के हित में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी। आरोप है कि इसके बावजूद 4 जून 2026 को 40-45

वर्षों से बंद पड़े सरकारी गोदामों में कुछ लोगों ने कथित रूप से कब्जा कर लिया।

कोर्ट के आदेश का हो रहा दुरुपयोग

सैनी ने आरोप लगाया कि वर्तमान कब्जाधारी न्यायालय के स्टे/आदेश का कथित रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम और पुलिस को शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

नगर निगम से कार्रवाई की मांग, आंदोलन की चेतावनी

एसोसिएशन ने आदर्श नगर निगम जोन के उप आयुक्त से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर कथित अवैध कब्जा हटाया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वैध वेंडर्स के हित में आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन की ओर से मामले से संबंधित JMC प्लेट नंबर 4139 की फोटो, वेंडर कार्ड और न्यायालय के आदेश भी संलग्न किए गए हैं। सरकारी गोदामों पर कब्जे और न्यायालय के आदेश के कथित दुरुपयोग संबंधी आरोप एसोसिएशन द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित विभाग/पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर खबर में शामिल किया जा सकता है।

इन्द्राराम प्रजापत एडवोकेट को पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव समन्वयक नियुक्त किया

मुमन पत्रिका

बालोतरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपते हुए इन्द्राराम प्रजापत एडवोकेट को पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव समन्वयक नियुक्त किया है। इन्द्राराम प्रजापत एडवोकेट को दी गई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा का आभार व्यक्त करते हुए प्रजापत को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि इन्द्राराम प्रजापत अपने संगठनात्मक अनुभव एवं सक्रियता के माध्यम से पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को मजबूत करेंगे तथा कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस नियुक्ति से पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में

उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस संगठन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरकर जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा।

बालोतरा में गूंजा मतदान का संदेश, 1200 छात्र-छात्राओं ने निकाली भव्य जागरूकता रैली

मुमन पत्रिका

बालोतरा, 24 अगस्त। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को जिला मुख्यालय बालोतरा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में बालोतरा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के करीब 1200 छात्र-छात्राओं सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, दिव्यांगजनों, स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने प्रतिभागियों को सामूहिक मतदान की शपथ

दिलाई तथा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में स्वीप गतिविधि के तहत आकर्षक एवं संदेशपरक रंगोली भी बनाई गई। रंगोली के माध्यम से मतदान के महत्व और मतदाता जागरूकता का प्रभावी संदेश दिया गया। रैली में शामिल छात्र-छात्राओं के हाथों में मतदाता जागरूकता से जुड़े संदेशों वाली रंग-बिरंगी तख्तियां और बैनर रहे। विद्यार्थी पूरे उत्साह के साथ 'मतदान जरूर करें ', 'मेरा वोट, मेरा अधिकार' सहित विभिन्न नारों के माध्यम से आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करते नजर आए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए न्यू बस स्टैंड पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। करीब 1200 छात्र-छात्राओं ने एक स्वर में मतदान के नारों के माध्यम से नागरिकों को लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का संदेश दिया। रास्तेभर विद्यार्थियों एवं अन्य प्रतिभागियों ने नारों और संदेशों के माध्यम से आमजन से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मतदाता जागरूकता रैली में दिव्यांगजनों की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। दिव्यांग प्रतिभागियों ने स्कूटी पर सवार होकर रैली में उत्साहपूर्वक भाग लिया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने सहभागिता के माध्यम से यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण है और मतदान के अधिकार का प्रयोग सभी की जिम्मेदारी है। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस जागरूकता रैली ने बालोतरा शहर में मतदान का संदेश बुलंद किया और आमजन को आगामी नगर निकाय चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकरी धनसिंह महेचा, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी घेवरचंद प्रजापत, सहायक जनसपंर्क अधिकारी नरेन्द्र कुमार, स्वीच प्रकोष्ठ से प्राचार्य दमन त्रिपाठी, उप प्रचार्य रामेश्वरी चौधरी, शारिरीक शिक्षक नरेन्द्र सिंह, व्याख्याता भैरू सिंह महेचा समेह विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता निभाई।

आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत औषधीय पौधों का पौधारोपण

मुमन पत्रिका

कुशतला। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद औषधालय आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष कुशतला में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में औषधालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए गए तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। पौधारोपण वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. विजय शंकर बैरवा, कंपाउंडर दिनेश कुमार वर्मा एवं छीतरमल वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान गिलोय, तुलसी, ग्वारपाठा (एलोवेरा), नागदमन एवं पत्थरचट्टा सहित विभिन्न बहुउपयोगी औषधीय पौधे रोपे गए। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. विजय शंकर बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद में औषधीय पौधों का विशेष महत्व है। ये पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ दैनिक जीवन में स्वास्थ्य संरक्षण और

प्राथमिक उपचार में भी उपयोगी होते हैं। उन्होंने आमजन से अपने घर एवं आसपास कम से कम एक औषधीय पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।

पुलिस उपाधीक्षक से मिला पंचायती राज शिक्षक संघ का शिष्टमंडल

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में संगठन के शिष्टमंडल ने पुलिस उपाधीक्षक शहर सवाई माधोपुर राजेंद्र कुमार मीना से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कानून व्यवस्था सहित विद्यालयों में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी ने बताया कि शिष्टमंडल द्वारा पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना का स्वागत किया गया तथा जिले में

कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने एवं आमजन में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सावधानियों के संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना ने संगठन के प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को कानून, साइबर अपराध एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

उन्होंने विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोग का संदेश दिया। संगठन के शिष्टमंडल में प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा, प्रदेश सलाहकार हरिशंकर गुर्जर, जिला सभाध्यक्ष प्रदीप भारद्वाज, जिला मंत्री ओमप्रकाश मीना, जिला संघर्ष समिति संयोजक अब्दुल वसीम, जिला उपाध्यक्ष भुवनेश्नर शर्मा, ब्लॉक संगठन मंत्री मोजीराम मीना, सुरेंद्र मालिया, जसराज सिंह चौहान आदि संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त सख्त, खाली भूखंडों में कचरा मिलने पर जताई नाराजगी

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर, 24 अगस्त। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया गंभीर नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के बीच शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और आमजन को साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को नगर परिषद आयुक्त ने स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों की बैठक लेकर शहर की सफाई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रदान किए। बैठक के दौरान आयुक्त ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित सफाई, कचरा उठाव, मुख्य मार्गों, बाजार कॉलोनियों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। उन्होंने सफाई निरीक्षक एवं जमादारों से सफाई कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सफाई कार्य में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त दलीप पूनिया ने खाली भूखंडों में लंबे समय से जमा कचरे को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खाली भूखंड कचरा संग्रहण स्थल नहीं बनें, इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में नियमित निगरानी की जाए। ऐसे स्थानों पर जमा कचरे को तत्काल हटाकर सफाई करवाने तथा दोबारा कचरा जमा नहीं हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों को अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारी निर्धारित क्षेत्रों में समय पर पहुंचकर सफाई कार्य करें और कचरा उठाव की व्यवस्था भी नियमित रूप से संचालित हो। उन्होंने कहा कि केवल सफाई करवाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सफाई के बाद कचरा समय पर उठाना भी जरूरी है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था कमजोर है, वहां विशेष ध्यान देकर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बैठक में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी, कचरा उठाव, खाली भूखंडों की सफाई तथा आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार क्षेत्र का निरीक्षण करते रहें और सफाई व्यवस्था को लेकर प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करें। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सफाई व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों को भी सक्रिय किया जा रहा है। बैठक में आगामी गणेश मेले को लेकर भी चर्चा की गई। आयुक्त ने मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य निरीक्षकों को पूरी रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में शिवराम मीना, अनमीत सिंह, इंद्रराज मीणा सहित बजरिया, आलनपुर एवं शहर में पदस्थापित सभी जमादार मौजूद रहे। फोटो कैप्शनः- 24 पीआरओ बैठक में स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों को निर्देश देते नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया।

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर,24 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश सहित सवाईमाधोपुर जिले के संबंधित अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट सभागार से वी.सी के माध्यम से जुड़े। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जिले के अधिकारियों से सीधे संवाद कर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिलेवार चुनाव तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से चुनाव कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उनका समाधान किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने मतदाता सूचियों में संशोधन एवं अद्यतन की स्थिति, दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हों और दिव्यांग एवं अन्य जरूरतमंद मतदाताओं को मतदान के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

चुनाव कार्य में लापरवाही पर जताई नाराजगी

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव तैयारियों में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरतने वाले जिलों एवं अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में चुनाव संबंधी कार्य पूरे करें और आयोग के निर्देशों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ पूरी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने चुनाव से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी समस्या का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

राजस्थान के आर्थिक विकास में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को मिलेगा 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान में स्थान

उद्योग, उद्यमिता, निर्यात, नवाचार एवं रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान देने वालों से 31 अगस्त तक नामांकन आमंत्रित

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर, 24 अगस्त। राजस्थान के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पहचान एवं व्यापक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान - आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसपेरिटी' पहल शुरू की गई है। इसके तहत राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक पंकज मीणा ने बताया कि पहल में उद्यमी, उद्योगपति, निर्यातक, प्रोफेशनल्स एवं आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। चयन में औद्योगिक विकास, व्यवसाय विस्तार, निर्यात, निवेश एवं रोजगार सृजन के साथ चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के प्रभावी संचालन, निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय संस्थानों के निर्माण में योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मिलेगा अवसरः- उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एवं ट्रेड, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाएं नामांकन कर सकेंगी। चयनित 100 आइकन्स में 55 महिलाओं (55 वर्ष से कम) एवं 45 पुरुषों (45 वर्ष से कम) को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चयनित व्यक्तियों की उपलब्धियों एवं विचारों को '100 आइकन्स कम्पेडियम' में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही डिजिटल लीडरशिप पोर्टल एवं रणनीतिक ज्ञान-विनिमय के माध्यम से उनकी विशेषज्ञता एवं अनुभव को व्यापक स्तर पर साझा करने के अवसर उपलब्ध होंगे। नामांकन प्रक्रिया 10 जुलाई 2026 से प्रारंभ है तथा इच्छुक पात्र व्यक्ति 31 अगस्त 2026 तक https// docs. google.com/ forms/d/e/ vFAIpQLSfRl_ RzCCRBUvx nFnEQUG {eDx_bkW& ClZE~xxp{~dE~etftȳQ / viewform के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र में सम्पर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने जिले के पात्र उद्यमियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स एवं संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं से इस पहल में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।

संपर्क पोर्टल, जनसुनवाई एवं बजट घोषणाओं की कलेक्टर ने की समीक्षा : अंतर्विभागीय प्रकरणों के त्वरित समाधान, विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं चुनाव तैयारियों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर, 26 अगस्त। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों, संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई प्रकरणों, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों तथा अंतर्विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई में दर्ज प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक प्रकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने तथा तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधाओं का संबंधित विभागों से समन्वय कर शीघ्र समाधान करने को कहा। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित सड़कों, निर्माण कार्यों, डीएलपी अवधि के कार्यों एवं लंबित कार्यों की भी समीक्षा की तथा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। डीएलपी अवधि की सड़कों का शत-प्रतिशत मरम्मत कार्य दिवाली पूर्व पूर्ण किया जाए। मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देशः- बैठक के दौरान जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निकाय चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की प्रकोष्ठवार समीक्षा की। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए सभी दायित्व समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर पेयजल, छाया, आवश्यक संसाधन एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का समय रहते भौतिक सत्यापन कराने को कहा। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी पुख्ता तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों के गठन, कार्मिक एवं ईवीएम रेंडमाइजेशन, प्रशिक्षण, मतदान केन्द्रवार रूट चार्ट एवं परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूर्ण करने को कहा। प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया एवं नवीन प्रावधानों की व्यवहारिक जानकारी देने तथा उनकी शंकाओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की प्रभावी मॉनिटरिंग, उल्लंघन की सूचना पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई तथा निर्वाचन नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं त्रुटिरहित व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता हो। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा, एसीईओ शैलेन्द्र सिंह, आयुक्त दलीप पूनिया सहित संबंधित जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी तथा निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो कैप्शनः- 24 पीआरओ 1 एवं 2 बैठक को सम्बोधित करते जिला कलक्टर काना राम।

बारिश के दौरान बढ़ जाती हैं सर्पदंश की घटनाएं : सर्पदंश पर झाड़-फूंक में समय न गंवाएं, तुरंत अस्पताल पहुंचें

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर, 24 अगस्त। बारिश के दौरान क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़-फूंक का चलन भी सामने आ रहा है। जागरूकता के अभाव में कई बार सर्पदंश पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक -फूंक कराई जाती है, जिससे समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण पीड़ित की जान को खतरा बढ़ जाता है। सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जेमिनी ने बताया कि जिले में आए दिन सर्पदंश की घटनाएं हो रही हैं। झाड़-फूंक में विश्वास और समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण सर्पदंश पीड़ित दम तोड़ देते हैं। सर्पदंश की स्थिति में एंटी स्नेक वेनम लगाए जाने से मौत पर काबू पाया जा सकता है। पहले एक घंटे का समय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सर्प के काटने पर पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सभी चिकित्सा संस्थानों पर एंटी स्नेक वेनम से उचित उपचार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सर्प के निवास स्थान बिलों में पानी भर जाने के कारण बरसात के दिनों में सर्प बाहर निकलते हैं, जिससे सर्पदंश का खतरा बढ़ जाता है। बचाव के लिए ग्रामीण रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, जमीन पर सोने से बचें तथा झाडियों और गंदगी से दूर रहें।

बिस्तर व कपड़ों को झटककर उपयोग करें। खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और रात में घास-फूस में जाने से बचें। उन्होंने बताया कि सभी सर्प जहरीले नहीं होते हैं। सर्पदंश होने पर संभव हो तो सर्प की पहचान करने का प्रयास करें, इससे उपचार में सहूलियत रहती है। जिला अस्पताल में जहरीले सर्प के काटने का उपचार होता है। सर्पदंश की स्थिति में घबराने के बजाय समय पर उपचार कराएं।

लहरिया उत्सव में सजी सावन की रंगीन छटा, महिलाओं ने प्रस्तुत किए गीत-भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर। दिगंबर जैन महिला मंडल आवासन मंडल के तत्वावधान में रविवार को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में पारंपरिक लहरिया उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सावन की हरियाली और राजस्थानी संस्कृति की छटा से सराबोर आयोजन में महिलाओं ने रंग-बिरंगे लहरिया परिधान पहनकर उत्साहपूर्वक सहभागिता की। महिलाओं ने कुमकुम का टीका लगाकर एक-दूसरे का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद पारंपरिक गीतों एवं भजनों का सिलसिला शुरू हुआ। गीत-भजनों पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्यों ने माहौल को उल्लासपूर्ण बना दिया। चूड़ियों की खनक और पायल की झंकार के बीच महिलाओं ने सावन के पारंपरिक रंगों का आनंद लिया। महिला मंडल की महामंत्री चंद्रकला बाकलीवाल एवं मंत्री वंदना बाकलीवाल के संयोजकत्व में दोपहर से देर शाम तक विभिन्न मनोरंजक खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी एवं प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन स्थल को लहरिया एवं सावन की थीम पर आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कल्पना पापड़ीवाल के संयोजन में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एकता गोधा एवं अर्चना जैन तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली दीपिका जैन श्रीमाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक-दूसरे को सावन की शुभकामनाएं दीं तथा सामाजिक एकता, पारिवारिक सौहार्द एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता से कार्यक्रम उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

बौंली में भाजपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, निकाय चुनाव में जीत का लिया संकल्प

मुमन पत्रिका

बौंली। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को बौंली में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और संगठन के प्रति समर्पण नजर आया। सम्मेलन में चुनाव प्रभारी ओमप्रकाश यादव, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल, विधायक प्रत्याशी राजेन्द्र कुमार मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, प्रधान कृष्ण पोसवाल, भाजपा नेता राजेश गोयल एवं मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियों एवं चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने बूथ प्रबंधन को मजबूत करने, प्रभावी जनसंपर्क अभियान चलाने तथा प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं।

कार्यकर्ताओं की एकजुटता, मेहनत और सक्रियता के बल पर भाजपा आगामी नगर निकाय चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों एवं केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने तथा एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का संकल्प लिया। सम्मेलन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आगामी निकाय चुनाव को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।

मुस्लिम समाज ने किया कांवड़ यात्रा का स्वागत, पेश की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

मुमन पत्रिका

बालोतरा। शहर में आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक सौहार्द की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। स्थानीय मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल के सामने समस्त मुस्लिम समाज बालोतरा संस्थान की ओर से कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। समस्त मुस्लिम समाज बालोतरा संस्थान के अध्यक्ष हाजी अब्दुल रहमान मोयला के नेतृत्व में समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान कांवड़ यात्रियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आपसी भाईचारे, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। मुस्लिम समाज की इस पहल से क्षेत्र में गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूती मिली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि धर्म और मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत, प्रेम और भाईचारा समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कांवड़ यात्रा के स्वागत के दौरान आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता की यह पहल बालोतरा में भाईचारे की सकारात्मक तस्वीर पेश करती नजर आई।

शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त सख्त, खाली भूखंडों में कचरा मिलने पर जताई नाराजगी

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर, 24 अगस्त। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया गंभीर नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के बीच शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और आमजन को साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को नगर परिषद आयुक्त ने स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों की बैठक लेकर शहर की सफाई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक के दौरान आयुक्त ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित सफाई, कचरा उठाव, मुख्य मार्गों, बाजार कॉलोनियों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। उन्होंने सफाई निरीक्षक एवं जमादारों से सफाई कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सफाई कार्य में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त दलीप पूनिया ने खाली भूखंडों में लंबे समय से

जमा कचरे को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खाली भूखंड कचरा संग्रहण स्थल नहीं बनें, इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में नियमित निगरानी की जाए। ऐसे स्थानों पर जमा कचरे को तत्काल हटाकर सफाई करवाने तथा दोबारा कचरा जमा नहीं हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों को अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारी निर्धारित क्षेत्रों में समय पर पहुंचकर सफाई कार्य करें और कचरा उठाव की व्यवस्था भी नियमित रूप से संचालित हो। उन्होंने कहा कि केवल सफाई करवाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सफाई के बाद कचरा समय पर उठाना भी जरूरी है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था कमजोर है, वहां विशेष ध्यान देकर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बैठक में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी, कचरा उठाव, खाली भूखंडों की सफाई तथा आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार क्षेत्र का निरीक्षण करते रहें और सफाई व्यवस्था को लेकर प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करें। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सफाई व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों को भी सक्रिय किया जा रहा है। बैठक में आगामी गणेश मेले को लेकर भी चर्चा की गई। आयुक्त ने मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य निरीक्षकों को पूरी रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में शिवराम मीना, अनमीत सिंह, इंद्रराज मीणा सहित बजरिया, आलनपुर एवं शहर में पदस्थापित सभी जमादार मौजूद रहे।
फोटो कैप्शनः- 24 पीआरओ बैठक में स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादारों को निर्देश देते नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया।

सरसों की तूड़ी से बदलेगी विद्यालय तस्वीर : सरसों की तूड़ी नीलामी से लोरवाडा ग्रामवासियों ने जुटाये 11 लाख, राज्य सरकार से विद्यालय विकास को मिलेंगे 27.50 लाख

मुमन पत्रिका

सवाई माधोपुर, 24 अगस्त। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले में संचालित अभिनव पहल 'भविष्य की उड़ान' एवं मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों के विकास की दिशा में प्रभावी माध्यम बन रही है। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोरवाड़ा के भौतिक विकास के लिए स्थानीय ग्रामवासियों ने सामूहिक पहल करते हुए सरसों की तूड़ी की नीलामी एवं जनसहयोग से प्राप्त 11 लाख रुपये की राशि विद्यालय को जनसहयोग के रूप में प्रदान की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा एवं ग्रामवासियों द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी देवी लाल मीणा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हरकेश लाल मीणा तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दिनेश कुमार गुप्ता की उपस्थिति में सहयोग राशि का चौक मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत जमा कराने के लिए जिला कलक्टर

कानाराम को सौंपा गया। जिला कलक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की इस सामूहिक पहल ने विद्यालय विकास में जनभागीदारी की भावना को मजबूती प्रदान की है। जनभागीदारी से बदल रही विद्यालयों की तस्वीरः- एडीपीसी हरकेश लाल मीणा ने कहा कि जुलाई 2022 से संचालित अभिनव पहल 'भविष्य की उड़ान' के माध्यम से स्थानीय समुदाय एवं विद्यालय परिवार की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जनसहभागिता से विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। 11 लाख के सहयोग पर मिलेगा 16.50 लाख का राज्यांशः- कार्यक्रम अधिकारी, समग्र शिक्षा हेमराज मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय को प्राप्त 11 लाख रुपये की सहयोग राशि पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 16 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त राज्यांश उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय को विकास कार्यों के लिए कुल लगभग 27 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि उपलब्ध राशि से विद्यालय में नवीन कक्षा-कक्षों का निर्माण, कक्षा-कक्षों की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक भौतिक संसाधनों का विकास किया जाएगा। इससे विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर सीबीईओ जगदीश नागर, एपीसी योगेश मीणा, आरपी राकेश कुमार मीणा, ग्रामवासी मूल्या पटेल, जगदीश गुर्जर, अम्बालाल, कैलाश गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर, गोपीचंद भगत, कालूराम गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।